पंजाब केसरी
TUE,21 APRIL 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 6

हिमाचल के स्कूलों में शुरू हुआ होलिस्टिक प्रोग्रैस कार्ड प्रोजैक्ट

■अब अंकों की जगह हुनर तय करेगा छात्र का भविष्य

धर्मशाला, 20 अप्रैल (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब अंकों के बजाय छात्रों के कौशल और व्यक्तित्व को मापने के लिए होलिस्टिक प्रोग्रैस कार्ड की शुरूआत की है। नई शिक्षा नीति के तहत सोमवार से शिमला और कांगड़ा जिलों के 10 स्कूलों में इसका पायलट प्रोजैक्ट शुरू कर दिया गया है।

सोमवार से शिमला और कांगड़ा जिले के 10 स्कूलों में इसे पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर लागू कर दिया गया है। अभी तक स्कूलों में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था, उसमें सिर्फ विषय के नंबर होते थे लेकिन अब जो होलिस्टिक प्रोग्रैस कार्ड लागू किया गया है, वह छात्र की पूरी तस्वीर पेश करेगा। इसमें छात्र की पढ़ाई के अलावा उसकी सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और व्यवहार को भी नंबर दिए जाएंगे।

बोर्ड ने इस बदलाव को जांचने के लिए शिमला और कांगड़ा के 10 स्कूलों को चुना है। इसमें सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं। बोर्ड यह देखेगा कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे प्रदेश के स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा।

इस नई पहल को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य हिमाचल की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। हमारा लक्ष्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को मापना है। फिलहाल हमने इसे पायलट प्रोजैक्ट के रूप में शुरू किया है, जिसकी सफलता के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा।

–डा. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

Dainik Jagran 21-04-2026

9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आरंभ

जागरण संवाद केंद्र, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की नींव रखी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए अब केवल अंकों पर निर्भर रहने के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और मानसिक विकास का आकलन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) के जरिए किया जाएगा। सोमवार से दो प्रमुख जिलों शिमला व कांगड़ा में इसका पायलट प्रोजेक्ट आरंभ कर दिया है।

डा. राजेश शर्मा ● जागरण आर्काइव

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड केंद्र सरकार की संस्था परख व एनसीईआरटी नई दिल्ली के सहयोग से तैयार किया है। इसे नौवीं से जमा दो कक्षा तक के छात्रों के लिए विकसित किया है। यह कार्ड डिजिटल प्रारूप में होगा, जिससे न केवल डाटा प्रबंधन आसान होगा, बल्कि यह अधिक पारदर्शी और विद्यार्थी केंद्रित भी बनेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ने शिमला व कांगड़ा के 10 स्कूलों में इसे लागू किया है। सरकारी व निजी स्कूलों में इसकी उपयोगिता जांची जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर फीडबैक लिया जाएगा। पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड में विषयों के अंक दर्ज होते थे, लेकिन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का दर्पण होगा। डा. राजेश शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक अंकों के साथ छात्र की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक-भावनात्मक कौशल को ट्रैक किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कार्ड तैयार किए गए हैं। डिजिटल होने के कारण शिक्षक और अभिभावक बच्चे की प्रगति को देख सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों में लागू करने की योजना है।

Divya Himachal 21-04-2026

स्कूलों में छात्रों का 360 डिग्री मूल्यांकन

होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के तहत अंकों के साथ कौशल व्यवहार-मानसिक विकास का होगा आकलन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए अब केवल अंकों पर निर्भर रहने के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और मानसिक विकास का आंकलन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) के जरिए किया जाएगा। 20 अप्रैल को प्रदेश के दो प्रमुख जिलों शिमला और कांगड़ा में इसका पायलट प्रोजेक्ट विधिवत रूप से आरंभ कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि यह प्रगति पत्रक केंद्र सरकार की संस्था परख और एनसीईआरटी नई दिल्ली के विशेष सहयोग से तैयार किया गया है। वर्तमान में इसे सेकेंडरी स्टेज यानी कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ने रणनीतिक रूप से शिमला और कांगड़ा जिलों का चयन किया है। इन जिलों के कुल 10 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता जांची जाएगी।

ऐसे बदलेगी तस्वीर पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड में जहां केवल विषयों के अंक दर्ज होते थे, वहीं एचपीसी विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का दर्पण होगा। डा. राजेश शर्मा के अनुसार शैक्षणिक अंकों के साथ-साथ छात्र की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक -भावनात्मक कौशल को ट्रैक किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कार्ड तैयार किए गए हैं। डिजिटल होने के कारण शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक बच्चे की प्रगति को वास्तविक समय (रियल टाइम) में देख सकेंगे।

- शिमला और कांगड़ा के 10 स्कूलों से हुई शुरुआत

> इस परियोजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य हिमाचल की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू करने की योजना है
>
> **डा. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड**

Amar Ujala 21-04-2026

कवायद

एनईपी-2020 के तहत बड़ा बदलाव, शिमला-कांगड़ा के 10 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

विद्यार्थियों के कौशल और व्यवहार का किया जाएगा 360 डिग्री मूल्यांकन

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के तहत प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ओर कदम बढ़ाए हैं।

अब छात्रों का मूल्यांकन केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उनके समग्र विकास को मापने के लिए '360 डिग्री' मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था का ट्रायल (पायलट प्रोजेक्ट) शिमला और कांगड़ा जिलों के 10 चयनित स्कूलों में शुरू कर दिया गया है।

नौवीं से 12वीं के छात्रों का बनेगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, डिजिटल होगी व्यवस्था

इस पहल के तहत विद्यार्थियों के केवल शैक्षणिक प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि उनके कौशल, व्यवहार, सामाजिक सहभागिता और मानसिक विकास का भी गहन आकलन किया जाएगा।

इसके लिए विशेष होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि यह प्रोग्रेस कार्ड केंद्र सरकार की संस्था परख और एनसीईआरटी के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्तमान में इसे सेकेंडरी स्तर (कक्षा 9 से 12) के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।

यह पूरी प्रणाली डिजिटल होगी, जिससे छात्रों के डेटा का प्रबंधन आसान होगा और मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी।

फीडबैक के बाद पूरे प्रदेश में होगा लागू

पायलट प्रोजेक्ट के लिए सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों को चुना गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को शामिल किया गया है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में इस मॉडल की उपयोगिता को परखा जा सके। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि पायलट चरण से प्राप्त फीडबैक और परिणामों के आधार पर आगामी समय में इस प्रणाली को पूरे प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू करने की योजना है।

स्कूलों में अब छात्रों का 360 डिग्री मूल्यांकन

हिमाचल में एचपीसी पायलट प्रोजेक्ट का आगाज

अनंत ज्ञान

◆ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शुरू

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए अब केवल अंकों पर निर्भर रहने के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और मानसिक विकास का आकलन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) के जरिए किया जाएगा। सोमवार से प्रदेश के दो प्रमुख जिलों शिमला और कांगड़ा में इसका पायलट प्रोजेक्ट विधिवत रूप से आरंभ कर दिया गया है।

एचपीसी से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर?

पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड में जहां केवल विषयों के अंक दर्ज होते थे, वहीं एचपीसी विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का दर्पण होगा।

परख व एनसीईआरटी के सहयोग से डिजिटल ढांचा तैयार

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि यह प्रगति पत्रक केंद्र सरकार की संस्था परख और एनसीईआरटी, नई दिल्ली के विशेष सहयोग से तैयार किया गया है। वर्तमान में इसे सेकेंडरी स्टेज यानी कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए विकसित किया गया है। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में होगा, जिससे न केवल डेटा प्रबंधन आसान होगा, बल्कि यह अधिक पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित भी बनेगा।

> **इस** परियोजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य हिमाचल की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू करने की योजना है।
>
> **डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड**

पहले चरण में शिमला और कांगड़ा जिले के 10 स्कूल चयनित

पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ने रणनीतिक रूप से शिमला और कांगड़ा जिलों का चयन किया है। इन जिलों के कुल 10 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है, जिनमें निम्नलिखित का समावेश है, राजकीय एवं निजी विद्यालयः सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता जांची जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रः भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर फीडबैक लिया जाएगा।

Himachal Dastak 21-04-2026

9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शुरू

धर्मशाला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए अब केवल अंकों पर निर्भर रहने के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और मानसिक विकास का आंकलन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) के जरिये किया जाएगा। सोमवार से प्रदेश के दो प्रमुख जिलों शिमला और कांगड़ा में इसका पायलट प्रोजेक्ट आरंभ कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि यह प्रगति केंद्र सरकार की संस्था परख और एनसीईआरटी, नई दिल्ली के विशेष सहयोग से तैयार किया गया है। वर्तमान में इसे सेकंडरी स्टेज यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विकसित किया गया है। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में होगा, जिससे न केवल डाटा प्रबंधन आसान होगा, बल्कि यह अधिक पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित भी बनेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ने रणनीतिक रूप से शिमला और कांगड़ा जिलों का चयन किया है। इन जिलों के कुल 10 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है, जिनमें राजकीय एवं निजी विद्यालय दोनों क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता जांची जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर फीडबैक लिया जाएगा।

सभी BDGIC केंद्रों पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध

विद्यालयों को शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

जागो ! कांगडा/ राकेश कुमार

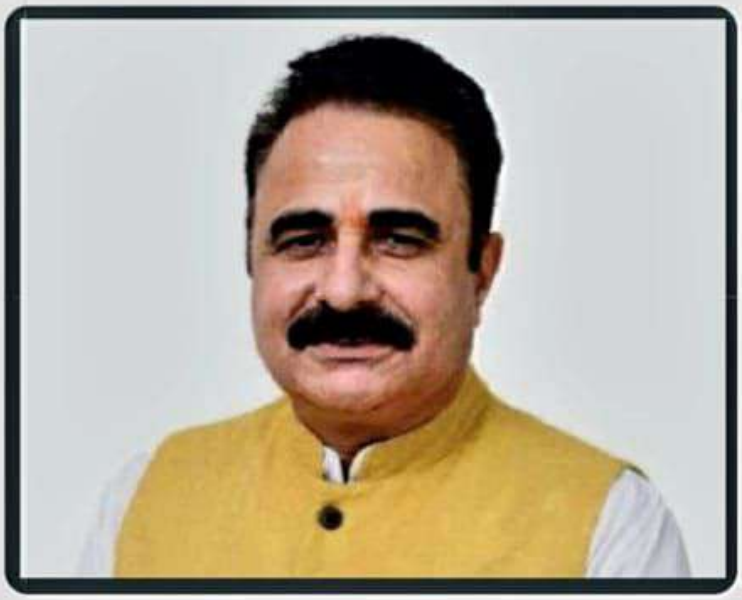

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने अवगत कराया है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी BDGIC (Book Distribution cum Guideline & Information Centres) केंद्रों पर पाठ्यपुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बोर्ड की प्राथमिकता है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।डॉ. शर्मा ने सभी सरकारी (Government) एवं बोर्ड से संबद्ध (affiliated) विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने नजदीकी BDGIC केंद्रों से आवश्यकतानुसार पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति (procurement) शीघ्र सुनिश्चित करें। विद्यालयों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप ही पुस्तकों की मांग सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की कमी या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न न हो।उन्होंने आगे कहा कि सभी संस्थान इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बोर्ड द्वारा इस प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है तथा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रदेश भर में निर्धारित सभी BDGIC (Book Distribution cum Guideline & Information Centres) केंद्रों पर पाठ्यपुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई पाठ्यसामग्री के अभाव में बाधित न हो।विद्यार्थियों का हित बोर्ड की प्राथमिकता-डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से संचालित करना और विद्यार्थियों को समय पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तकों की छपाई और केंद्रों तक उनकी पहुंच का कार्य पूरा कर लिया गया है, अब स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें समय पर प्राप्त करें।

APRIL 21, 2026 TUESDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

HPBOSE LAUNCHES HIGH-TECH 360° ASSESSMENT TO MAP STUDENT PERSONALITIES

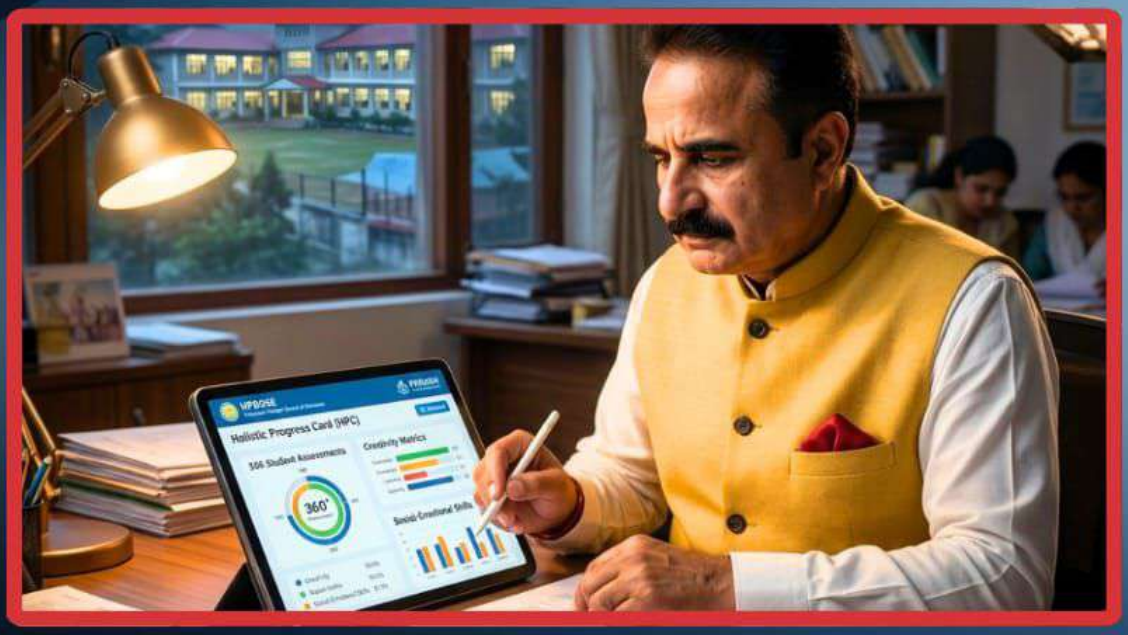

Sunny Mahajan | Dharamshala

In a significant move toward modernizing the education system, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has officially launched a revolutionary "Holistic Progress Card" (HPC) pilot project. Aligned with the National Education Policy (NEP-2020), this initiative shifts the focus from traditional marks-based testing to a comprehensive 360-degree assessment of a student's growth.

The project commenced on Monday, April 20, 2026, across ten selected schools in the Shimla and Kangra districts. This digital framework, developed in collaboration with PARAKH and NCERT New Delhi, is currently tailored for students in classes 9 through 12. Unlike standard report cards that only highlight academic scores, the HPC tracks a student's creativity, critical thinking, and social-emotional skills.

Dr. Rajesh Sharma, Chairman of HPBOSE, emphasized that the digital nature of these cards ensures transparency and allows parents and teachers to monitor a child's multifaceted development in real-time. By testing the project in both urban and rural settings, as well as private and government schools, the board aims to gather diverse feedback before implementing the system statewide.